सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
1911 से आपके लिए "केंद्रित" "CENTRAL" TO YOU SINCE 1911
केन्द्रीय कार्यालय
Central Office

CO:MBD:2021-22:71

02nd June, 2021

National Stock Exchange of India Limited Listing Department Exchange Plaza, Plot No.C/1, 'G' Block Bandra-Kurla Complex Bandra (E), Mumbai-400 051 **Scrip Code - CENTRALBK**	BSE Ltd. Corporate Relationship Dept. Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort Mumbai 400001 **Scrip Code - 532885**

Dear Sir/Madam,

Sub : Notice of Extra-ordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank for election of ONE Shareholder Director - Press Clippings of Notice of Extra-ordinary General Meeting (EGM)

Please refer to our letter no. CO:MBD:2019-20:68 dated 1st June, 2021 submitting press clipping of EGM notice published in Business Standard (English) on 01st June 2021.

Further to this, we have also published Notice of EGM in Business Standard (Hindi) in All Editions and Tarun Bharat (Marathi) in Mumbai Edition on 02nd June 2021.

A copy of such press clippings published in abovesaid newspapers is enclosed herewith.

Please take the above on your record.

Thanking you,

Yours faithfully,

For CENTRAL BANK OF INDIA

इंडिया / CENTRAL BANK OF INDIA मर्चेंट बैंकिंग विभाग, कें.का. Merchant Banking Division, C.O. मुंबई / MUMBAI

ANAND KUMAR DAS
DEPUTY GENERAL MANAGER/
COMPANY SECRETARY

चंदर मुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 • दूरध्वनी : 2202 6428, 6638 7777 • फैक्स : (91-22) 2204 4336
चंदर मुखी, नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 • दूरध्वनी : 2202 6428, 6638 7777 • फैक्स : (91-22) 2204 4336
Chander Mukhi, Nariman Point, Mumbai - 400 021 • Tel. : 2202 6438, 6638 7777 • Fax : (91-22) 2204 4336
www.centralbankofindia.co.in

आईएफएससी के लिए ऑफ मार्केट हस्तांतरण की इजाजत

ऐश्ली कुटिन्हो
मुंबई, 1 जून

बाजार नियामक सेबी का फैसला

- सेबी के पास विदेशी फंडों के तौर पर पंजीकृत एफपीआई अगर आईएफएससी आना चाहते हैं तो उन्हें नए एफपीआई लाइसेंस की दरकार होगी
- उन्हें प्रतिभूतियों का हस्तांतरण अपने पुराने डीमैट खाते से नए डीमैट खाते में करना होगा, जिस पर आईएफएससी एफपीआई का टैग लगा होगा
- चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश स्वामी ने कहा, सभी एफपीआई को पुराने डीमैट खाते की प्रतिभूतियों को एक्सचेंज पर बेचना होगा और नए डीमैट खाते में उन्हें खरीदना होगा

बाजार नियामक सेबी ने प्रतिभूतियों के ऑफ मार्केट हस्तांतरण की अनुमति दी है ताकि विदेशी फंडों को गुजरात के इंटरनैशनल फाइनैंशियल सर्विसेज सेंटर (आईएफएससी) में फंड लाने में आसानी हो। सेबी का नियम अभी एफपीआई और अलग-अलग परमानेंट अकाउंट नंबर के बीच प्रतिभूतियों के कैशलेश ट्रांसफर की इजाजत नहीं देता।

बाजार नियामक ने मंगलवार को कहा, यह फैसला लिया गया है कि एफपीआई (मूल फंड या अपने पूर्ण स्वामित्व वाले एसपीवी) अपनी प्रतिभूतियां के ऑफ मार्केट एकमुश्त हस्तांतरण के लिए डीडीपी से संपर्क कर सकते हैं। जांच परख (ड्यू डिलिजेंस) के बाद डीडीपी इस तरह के ऑफ मार्केट एकमुश्त हस्तांतरण की इजाजद दे सकता है।

चार्टर्ड अकाउंटेंट सुरेश स्वामी ने कहा, यह स्वागतयोग्य कदम है। आईएफएससी में ऐसा फंड लाने की लागत घटेगी और आईएफएससी को और आकर्षक गंतव्य बना देगा।

सेबी के पास विदेशी फंडों के तौर पर पंजीकृत एफपीआई अगर आईएफएससी आना चाहते हैं तो उन्हें नए एफपीआई लाइसेंस की दरकार होगी। उन्हें प्रतिभूतियों का हस्तांतरण अपने पुराने डीमैट खाते से नए डीमैट खाते में करना होगा, जिस पर आईएफएससी एफपीआई का टैग लगा होगा।

स्वामी ने कहा, सभी एफपीआई को पुराने डीमैट खाते की प्रतिभूतियों को एक्सचेंज पर बेचना होगा और नए डीमैट खाते में उन्हें खरीदना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह खातों को विलय के कारण हुआ या फिर रीलोकेशन के कारण। मौजूदा नियम मल्टी इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की स्थिति में ही प्रतिभूतियों के ऑफ मार्केट हस्तांतरण की इजाजत देता है, जहां लाभार्थी स्वामित्व एक हो और उनका कॉमन पैन हो।

इस साल वित्त विधेयक में हुए संशोधन से विदेशी फंडों के पूर्ण स्वामित्व वाले एसपीवी को गुजरात के आईएफएससी फंड में प्रतिभूतियों के हस्तांतरण की इजाजत दी गई है। साथ ही आईएफएससी फंड को यूनिट या तो विदेशी फंड के निवेशकों को जारी करने या फिर विदेशी फंडों को जारी करने में सक्षम बनाया गया था।

यह कदम फंड मैनेजर को जरूरी लचीलापन मुहैया कराने के लिए उठाया गया कि या तो वह फंड के पूरे ढांचे को आईएफएससी में शिफ्ट कर दे या फिर मास्टर फीडर स्ट्रक्चर अपनाए।

कई दो स्तर वाले फंड ढांचे मसलन लक्जमबर्ग-मॉरीशस-इंडिया या केमन-मॉरीशस-इंडिया आईएफएससी की ओर जाने के मामले में विचार करने वाले पहले फंड हो सकते हैं, क्योंकि वैश्विक फंडों के निवेशकों को प्रभावित किए बिना उसे लागू करना अपेक्षाकृत आसान होगा। यह कहना है विशेषज्ञों का।

टाटा संस के बोर्ड की दौड़ में शामिल हैं नोएल, झवेरी!

बीएस संवाददाता
मुंबई, 1 जून

खुदरा श्रृंखला ट्रेंट के चेयरमैन नोएल टाटा और सिटीबैंक इंडिया के पूर्व भारतीय प्रमुख प्रमीत झवेरी टाटा संस के निदेशक मंडल में शामिल होने वालों में अग्रणी नाम हैं। टाटा संस, टाटा समूह की होल्डिंग कंपनी है।

दोनों अभी टाटा ट्रस्ट्स के निदेशक मंडल में शामिल हैं और टाटा संस के निदेशक मंडल में ट्रस्ट्स का प्रतिनिधित्व करेंगे। सीएनबीसी टीवी 18 ने यह खबर दी है। टाटा संस ने इस रिपोर्ट पर टिप्पणी करने से मना कर दिया।

अभी टीवीएस समूह के चेयरमैन और टाटा ट्रस्ट के वाइस चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन टाटा संस के बोर्ड में टाटा ट्रस्ट्स का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। टाटा समूह के संरक्षक रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा को फरवरी 2019 में तीन साल के लिए टाटा ट्रस्ट के बोर्ड में शामिल किया गया था। झवेरी पिछले साल फरवरी में दोराबजी ट्रस्ट्स से जुड़े थे।

टाटा संस की सालाना आम बैठक (एजीएम) सामान्यत: अगस्त में होती है और अगर ये दो नियुक्तियां होती हैं तो उसे बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी लेनी होगी। टाटा ट्रस्ट्स के पास टाटा संस की 66 फीसदी हिस्सेदारी है, वहीं प्रतिस्पर्धी मिस्त्री परिवार के पास कंपनी की 18.5 फीसदी हिस्सेदारी है।

एशियाई बाजार कर सकते हैं बेहतर प्रदर्शन, भारत पर हैं ओवरवेट : नोमूरा

इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा आदि हैं ब्रोकरेज फर्म नोमूरा के पसंदीदा दांव

पुनीत वाधवा
नई दिल्ली, 1 जून

वैश्विक पोर्टफोलियो में एशियाई बाजारों में उम्दा प्रदर्शन करने की क्षमता है, नोमूरा की हालिया रिपोर्ट में ये बातें कही गई है। नोमूरा ने अपने एशियाई पोर्टफोलियो में (जापान को छोड़कर) भारत पर ओवरवेट रुख बरकरार रखा है। भारत के संदर्भ में रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा और डॉ. रेड्डीज नोमूरा के पसंदीदा शेयर हैं।

वैश्विक शोध व ब्रोकरेज फर्म ने मार्च 2022 के लिए निफ्टी-50 का लक्ष्य 15,340 कर दिया हैं, जो पहले दिसंबर 2021 के लिए 14,680 था और फर्म ने इसे अभी बरकरार रखा है। नोमूरा का ककहना है कि आने वाले समय में वह भारत की आर्थिक रफ्तार के बजाय कंपनियों की आय पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करेगी। आगर आर्थिक रफ्तार सीमा से ऊपर टिकी रहती है तो भारतीय कंपनी जगत लाभ में सुधार के जरिये बेहतर आय दर्ज कर सकती है।

नोमूरा के विश्लेषक जिम मैककैफरटी ने अपने एपीएसी इक्विटी रिसर्च के संयुक्त प्रमुख के साथ लिखा है, हमें लगता है कि बॉन्ड के सापेक्ष इक्विटी अभी भी आकर्षक दिख रहा है, जब तक कि प्रतिफल एक ऐसे स्तर पर नहीं पहुंच जाता जहां बॉन्ड आकर्षक बन जाए। निवेशक एशियाई इक्विटी पर सतर्क नजर आ रहे हैं, लेकिन हमारा मानना हैं कि एशिया में वैश्विक पोर्टफोलियो में उम्दा प्रदर्शन करने की क्षमता है।

एमएससीआई एशिया (जापान को छोड़कर) के लिए 2021-22 के आखिर का उनका लक्ष्य 900/974 है, जो 2021-22 में आय में लगातार हो रहे सुधार के अनुमान पर है। यह मौजूदा स्तर से 27 से 38 फीसदी का रिटर्न बैठता है, जहां इंडेक्स अभी है। कुल मिलाकर एशियाई इक्विटी पर मध्यम अवधि के लिहाज से नोमूरा सकारात्मक बनी हुई है।

नोमूरा ने कहा, शेयर का चयन अहम होगा और जिस रणनीति की सिफारिश की गई है वह अपरिवर्तित है। महंगाई और जिंसों की कीमतें, दरों का परिदृश्य, आय पर निराशा (खास तौर से एशिया के तकनीकी क्षेत्र से), नियमन, उच्च कर और एशियाई क्षेत्र में बढ़ता सामाजिक तनाव और कोविड संक्रमम एशियाई इक्विटी के मामले में उनके लिए अहम जोखिम है। देश के लिहाज से उनकी प्राथमिकता अभी भी उत्तर एशिया है, न कि दक्षिण या दक्षिण पूर्व एशिया।

समस्याओं के बावजूद विश्लेषकों को भा रहे एफएमसीजी शेयर

उपभोक्ता मांग में कमजोरी से एफएमसीजी क्षेत्र पर दबाव पड़ा है

पुनीत वाधवा
नई दिल्ली, 1 जून

बढ़ती उत्पादन लागत की अल्पावधि चुनौतियों और ग्रामीण तथा शहरी भारत दोनों पर दूसरी लहर का प्रभाव पड़ने की वजह से उत्पादों के लिए कमजोर मांग की आशंका के बावजूद विश्लेषक एफएमसीजी कंपनियों के शेयरों पर उत्साहित बने हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि सूचकांक वित्त वर्ष 2022 की दूसरी छमाही में प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करेगा।

आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले एक साल में, मूंगफली तेल, सरसों तेल, वनस्पती, सोया तेल, सूरजमुखी तेल और पाम तेल जैसी मुख्य जिंसों की कीमतें 20 प्रतिशत से लेकर 60 प्रतिशत के बीच चढ़ी हैं। विश्लेषकों का कहना है कि इस पृष्ठभूमि में, एफएमसीजी क्षेत्र पर दबाव बढ़ा है। इसकी वजह उपभोक्ता मांग में आई कमजोरी के साथ साथ ऊंची कच्चे तेल, पाम तेल और वैश्विक खाद्य कीमतों की वजह से संभावित मार्जिन दबाव है।

ऐंटीक स्टॉक ब्रोकिंग के पंकज छाओछरिया और धीरेंद्र तिवारी ने एक ताजा रिपोर्ट में लिखा है, 'ऊंचे बेरोजगार स्तर को देखते हुए आईआईपी उपभोक्ता वस्तुओं में कमजोरी अगले कुछ महीनों तक बनी रह सकती है।'

विश्लेषकों का मानना है कि कंपनियां कच्चे माल (तेल) में भारी तेजी का बोझ आने वाले समय में कम करने में सक्षम होंगी।

दूसरी तरफ, उपभोक्ता बिस्कुट, चाय, चीनी, नूडल्स, साबुन और शैम्पू जैसे जरूरी सामान की खरीदारी बरकरार रखेंगे। हालांकि वे अब इन श्रेणियों में महंगे उत्पादों की खरीद से परहेज कर सकते हैं। उनके अनुसार, खपत को मदद का अन्य कारण लगातार तीसरे साल सामान्य मॉनसून की संभावना है।

इससे कृषि उपज को मदद मिलेगी, मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने और अर्थव्यवस्था को ताजा लॉकडाउन के बाद पुनर्जीवित करने में मदद मिलेगी।

इक्विनोमिक्स रिसर्च के संस्थापक एवं मुख्य निवेश अधिकारी जी चोकालिंगम ने कहा, 'बढ़ती कीमतों का पूरा बोझ ग्राहकों पर डालना तुरंत संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि कंपनियां ग्रामीण और शहरी भारत पर कोविड के प्रभाव को महसूस कर रही हैं। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हो सकता है। लोग जरूरी सामान की खरीदारी बरकरार रखेंगे, लेकिन ऊंची कीमत वाले उत्पादों के लिए मांग प्रभावित हो सकती है। सामान्य मॉनसून से मदद मिलेगी।'

दलाल पथ पर, निफ्टी एफएमसीजी सूचकांक वित्त वर्ष 2022 में अब तक कमजोर रहा है और इसमें 0.1 प्रतिशत की गिरावट आई, जबकि निफ्टी-50 में करीब 5 प्रतिशत की तेजी रही। कुछ खास शेयरों के संदर्भ में बात की जाए तो पता चलता है कि गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, मैरिको, यूनाइटेड स्पिरिट्स और कोलगेट-पामोलिव में इस अवधि के दौरान 9 से लेकर 16 प्रतिशत के बीच तेजी आई, जबकि ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान यूनिलीवर (एचयूएल) और आईटीसी में 6 प्रतिशत तक की कमजोरी दर्ज की गई।

आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी में मुख्य निवेश अधिकारी महेश पाटिल का कहना है, 'जनसांख्यिकी, पति व्यक्ति आय, पहुंच स्तर और संगठित क्षेत्र के प्रति सकारात्मक बदलाव को देखते हुए भारत की खपत संबंधित सफलता अभी शुरू ही हुई है। हम कुछ वर्षों में मुद्रास्फीति में वृद्धि देखेंगे, लेकिन एफएमसीजी कंपनियों के पास उत्पाद मिश्रण के साथ साथ मूल्य निर्धारण ताकत का विकल्प है और वे बढ़ती लागत का ज्यादातर बोझ उपभोक्ताओं पर डालने में सक्षम होंगी।'

भले ही संपूर्ण एफएमसीजी क्षेत्र का प्रदर्शन कमजोर रहा है, लेकिन जेफरीज के विश्लेषकों का मानना है कि भविष्य में इस क्षेत्र का प्रतिफल मजबूत बना रह सकता है। उनका कहना है कि सामान्य चिंता ऊंचा मूल्यांकन मल्टीपल भी है, जिस पर एफएमसीजी कंपनियों कारोबार (40-60 गुना पर) कर रही हैं और भविष्य में यह नीचे आ सकता है। उन्होंने एक रिपोर्ट में कहा है, 'एफएमसीजी कंपनियां जिस मल्टीपल पर कारोबार कर रही हैं, वह उनके स्वयं के ऐतिहासिक औसत से ऊपर है।'

भारत में होगी 2-3 लाख करोड़ रु. की रिकॉर्ड इक्विटी आपूर्ति

पुनीत वाधवा
नई दिल्ली, 1 जून

- जेफरीज का कहना है कि 40 फीसदी हिस्सा आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के जरिए जुटाया जा सकता है
- जोमैटो व पेटीएम भी इस साल सूचीबद्ध होने की तैयारी में है

भारतीय इक्विटी बाजार अब तक के सर्वोच्च स्तर के पास कारोबार कर रहे हैं और यहां वित्त वर्ष 22 में 2-3 लाख करोड़ रुपये की रिकॉर्ड इक्विटी की आपूर्ति हो सकती है और इसका 40 फीसदी हिस्सा आरंभिक सार्वजनिक निर्गम के जरिए जुटाया जा सकता है। हालांकि कॉरपोरेट इक्विटी की आपूर्ति की वास्तविक मात्रा संस्थागत निवेश पर निर्भर करेगी और यह नए निवेशकों को भी ला सकती है। जेफरीज के नोट में ये बातें कही गई है।

जेफरीज के प्रबंध निदेशक महेश नंदूरकर ने अभिनव सिन्हा के साथ लिखी रिपोर्ट में कहा है, भारत के इंटरनेट स्पेस में परिपक्वता, सरकार का विनिवेश कार्यक्रम और पारंपरिक तौर पर वित्तीय तौर पर प्रतिभूतियां जारी करने वाली बड़ी कंपनियों का इसमें वर्चस्व रहेगा, लेकिन करीब एक फीसदी मार्केट कैप पर आपूर्ति सीमा के भीतर ही होगी। हमारा विश्लेषण बताता है कि शुद्ध इक्विटी आपूर्ति विगत में तेजी के मजबूत बाजार में आसानी से 1 फीसदी के पार निकल गया है और अब 30 से 40 अरब डॉलर की सकल इक्विटी समाहित हो सकती है।

जेफरीज के मुताबिक, वित्त वर्ष 21 में इक्विटी की आपूर्ति अनुमानित तौर पर 24 अरब डॉलर रही, जो तीन साल का उच्चस्तर है। पिछले दशक में इक्विटी के जरिए रकम जुटाने में आरंभिक सार्वजनिक निर्गम का योगदान करीब 27 फीसदी पर स्थिर रहा है। भारत का परिपक्व इंटरनेट क्षेत्र हालांकि इस प्रवृत्ति को आगे दो बड़ी कंपनियों जोमैटो व पेटीएम के साथ बदल सकता है, डो इस वित्त वर्ष में सूचीबद्ध होने की तैयारी कर रही हैं।

देश की सबसे बड़ी ऑनलाइन बीमा कंपनी पॉलिसी बाजार भी आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है और उसकी योजना आईपीओ से 4,000 करोड़ रुपये जुटाने की है। जोमैटो पहले ही विवरणिका का मसौदा सेबी के पास जमा करा चुकी है और यह कंपनी इसके जरिये 8,250 करोड़ रुपये जुटाने पर विचार कर रही है।

आनंद राठी के एस. सिंघल ने एक नोट में कहा है, कंपनी इस रकम का एक हिस्सा खुद के दम पर या विलय-अधिग्रहण के जरिए आगे बढ़ने पर करेगी। बाकी रकम का इस्तेमाल कंपनी का सामान्य कामकाज पर होगा। यह आईपीओ यूनिकॉर्न के लिए भारतीय निवेशकों की परीक्षा भी होगी।

दूसरी ओर, पेटीएम का इरादा इस साल करीब 22,000 करोड़ रुपये जुटाने की है। अगर यह कामयाब रहा तो किसी भारतीय कंपनी का सबसे बड़ा आईपीओ होगा। इससे पहले कोल इंडिया साल 2010 में 15,475 करोड़ रुपये जुटा चुकी है।

कोविड से मुकाबले के लिए आईटीसी इन्फोटेक की पहल

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 1 जून

मझोले आकार की सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी आईटीसी इन्फोटेक ने कोविड-19 संकट से मुकाबले के लिए कई पहलें शुरू की हैं। इनमें कंपनी के ग्राहकों और भागीदारों को कोविड से मुकाबले में उनके कर्मचारियों और संबंधितयों की मदद करने जैसी पेशकशें शामिल हैं। आईटीसी इन्फोटेक की रणनीति तीन स्तंभों पर केंद्रित है। इनमें संक्रमण के प्रसार को नियंत्रण करने के लिए रोकथाम उपाय, प्रभावितों की मदद करना और ग्राहकों, भागीदारों तथा सरकारी अधिकारियों के साथ भागीदारी शामिल है।

कंपनी पात्र कर्मचारियों और उनके परिवारों को कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीकरण कराने के लिए प्रोत्साहित कर रही है और वह अपनी पूरी वैश्विक कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए टीकाकरण का खर्च वहन करेगी। इसके अलावा, आईटीसी इन्फोटेक भारत में अपने सभी कार्यालयों में कर्मचारियों और उनके संबंधियों के लिए टीकाकरण अभियान आयोजित करने के लिए विभिन्न स्थानों की भी तलाश कर रही है।

कंपनी ने रैपिड रेस्पॉंस लीडर्स (आरआरएल) बनाने के लिए वरिष्ठ प्रबंधकों का चयन किया है। प्रत्येक आरआरएल के लिए कुछ कर्मियों का एक समूह निर्धारित किया गया है जो कर्मचारियों की सहायता के लिए उनके साथ अतिरिक्त संवाद एवं समर्थन मुहैया कराने की जिम्मेदारी संभालेगा।

कंपनी ने संसाधनों तक पहुंच को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों के लिए ऐप भी शुरू किया है।

छत्रपति शिवाजी रेलवे स्टेशन के कायाकल्प की दौड़ में कई दिग्गज

बीएस संवाददाता
नई दिल्ली, 1 जून

मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन (सीएसएमटी) के पुनर्विकास के लिए 9 बोलीदाताओं ने अपने प्रस्ताव सौंपे हैं।

भारतीय रेलवे स्टेशन विकास निगम (आईआरएसडीसी) के एक बयान में कहा गया है कि ये बोलीदाता हैं अदाणी रेलवेज ट्रांसपोर्ट, जीएमआर एंटरप्राइजेज, गोदरेज प्रॉपर्टीज, ओबरॉय रियल्टी, आईएसक्यू एशिया इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स, कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन, एंकरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स होल्डिंग्स, ब्रुकफील्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड-4, और मॉरीबस होल्डिंग्स।

इन चयनित बोलीदाताओं ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (आरएफपी) चरण में प्रवेश किया है। पिछले रिक्वेस्ट फॉर कुटेशन (आरएफक्यू) चरण में 10 बोलीदाता थे और कीस्टोन रियल्टर्स ऐसी एकमात्र कंपनी रही, जो पात्र नहीं थी।

अनुमान है कि इस स्टेशन की पुनर्विकास लागत (अनिवार्य लागत) 1,642 करोड़ रुपये है जिसमें वित्त पोषण संबंधित लागत भी शामिल है।

आईआरएसडीसी ने कहा है कि आवेदनों का मूल्यांकन बोलीदाताओं की वित्तीय क्षमता के आधार पर किया गया था। इसके लिए उन्हें अन्य शर्तों के साथ साथ पूर्ववर्ती वित्त वर्ष की समाप्ति तक 821 करोड़ रुपये की न्यूनतम निवेश पूंजी अनिवार्य है।

पूरी बोली प्रक्रिया दो चरण वाली है जिसमें आरएफक्यू और आरएफपी को शामिल किया गया है। आईआरएसडीसी ने कहा है कि आरएफपी चरण के बाद चयनित बोलीदाता को सीएसएमटी रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
प्रधान कार्यालय: चंदरमुखी नरीमन पॉइन्ट, मुम्बई – 400 021

सूचना

एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयर धारकों की असाधारण सामान्य बैठक बुधवार दिनांक 30 जून, 2021 को पूर्वान्ह 11.00 बजे चंदरमुखी, नरीमन प्वाइंट, मुंबई – 400 021 स्थित बैंक के प्रधान कार्यालय (बैठक का प्रस्तावित स्थल) में वीडिओ कॉन्फरेंस (वीसी) / अन्य दृश्य श्रव्य माध्यम (ओएवीएम) से निम्नलिखित कार्यकलाप के संपादन हेतु आयोजित की जाएगी.

कार्यसूची मद : शेयर धारकों के निदेशक का चुनाव

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों के अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (इसके बाद इसे "अधिनियम" कहा गया है की धारा 9 (3) (i) सह पठित बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद इसे "विनियम अधिनियम" कहा गया है.), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद इसे "योजना" कहा गया है), अधिनियम की धारा 19 के अनुसरण में बनाए गए सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठकें) विनियम, 1998 (इसके बाद इसे "विनियम" कहा गया है) और अधिसूचना संख्या डीबीआर.अपार्ट सं.9/29.67.001/2019-20 दिनांक 2 अगस्त, 2019 (इसके बाद इसे " आरबीआई मास्टर निर्देश" कहा गया है और इसमें आगे संशोधन यदि कोई हो) के माध्यम से जारी पीएसबी के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उपयुक्त और उचित' मानदंड पर आरबीआई मास्टर निर्देश सहपठित भारत सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में गैर-सरकारी निदेशकों के रूप में विचार के लिए जारी दिशानिर्देश दिनांक 25 मार्च, 2015 और दिनांक 20 जुलाई 2016 (इसके बाद "भारत सरकार के दिशानिर्देश" रूप में संदर्भित किया गया है और इसके संशोधन, यदि कोई हो) के अनुसार निम्न संकल्प पारित कर केंद्र सरकार के अलावा बैंक के शेयरधारकों में से एक निदेशक का चयन करना:

"संकल्पि किया जाता है कि संबंधित योजना, उसके तहत बनाये गये विनियमों, आरबीआई मास्टार दिशानिर्देशों और भारत सरकार के दिशानिर्देशों के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 (3) (i) के अनुसार केंद्र सरकार से अतिरिक्त शेयरधारकों में से एक निदेशक चुना गया है, एतद्द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में चयनित को दिनांक 01 जुलाई 2021 से कार्यालय संभालना है और वे इस प्रकार कार्य संभालने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के पूरा होने तक पद धारण करेंगे"

नोट :

1. **वीडिओ कॉन्फरेंस(वीसी) / अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम (ओएवीएम) से असाधारणसामान्य बैठक का आयोजन**
कोविड-19, महामारी के चलते हुए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के परिपत्र संख्या सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020, तथा सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी2/ सीआईआर/पी/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021, सहपठित,कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने परिपत्र संख्या 20, दिनांक 5 मई, 2020, परिपत्र संख्या 14 दिनांक 8 अप्रैल, 2020 और परिपत्र संख्या 17, दिनांक 13 अप्रैल, 2020, परिपत्र सं. 22 दिनांक 15 जून, 2020, परिपत्र सं. 33 दिनांक 28 सितम्बमर, 2020,परिपत्र सं. 39 दिनांक 31 दिसम्ब र, 2020 और परिपत्र सं.2 दिनांक 13 जनवरी, 2021 (इसके बाद इन्हें सामूहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र" कहा जायेगा) के माध्यम से एक स्थल पर उपस्थित हुए बिना, वीडिओ कॉन्फरेंस(वीसी) अथवा अन्य दृश्य-श्रव्य माध्यम (ओएवीएम) से असाधारणसामान्य बैठक का आयोजन करने की अनुमति प्रदान की है. इन एमसीए परिपत्रों और सेबी(सूचीबद्ध प्रकटीकरण एवं अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुपालन में बैंक के सदस्यों की असाधारणसामान्य बैठक वीसी/ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है. वीडियो कांफ्रेंस (वीसी) अथवा अन्या दृश्या-श्रव्ये माध्योम (ओएवीएम) से असाधारण सामान्य बैठक में सहभागिता करने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु कृपया असाधारण सामान्यय बैठक का नोटिस देखें जिसे शेयरधारकों को ई- मेल किया जा रहा है तथा बैंक की वेबसाइट www.centeralbankofindia.co.in पर 'इंवेस्टध्र रिलेशन" लिंक के अंतर्गत अपलोड किया जा रहा है.
2. **रिमोट ई-वोटिंग**
सेबी (सूचीबद्ध प्रकटीकरण एवं अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के नियम 44 सह पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सुविधा पर सेबी के 9 दिसंबर, 2020 के परिपत्र के अनुपालन में बैंक, वैकल्पिक माध्यईम के तौर पर रिमोट ई वोटिंग सुविधा सहर्ष प्रस्तारवित करता है ताकि सदस्येगण अपने वोट इलेक्ट्रॉनिक रूप से कर पाएं. बैंक द्वारा लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि., बैंक के रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ रिमोट ई-वोटिंग को सुलभ बनाने के लिए आवश्यक व्यावस्थाएं कर ली गयी है.रिमोट ई-वोटिंग की अवधि रविवार, दिनांक 27 जून, 2021 को पूर्वान्हय 10.00 बजे से मंगलवार, दिनांक 29 जून, 2021 को सायं 5.00 बजे तक है. इस अवधि के दौरान नियत (कट ऑफ) तारीख अर्थात बुधवार , दिनांक 23 जून, 2021 को भौतिक रूप से या डीमेट रूप में शेयर रखनेवाले बैंक के शेयरधारक अपने वोट इलेक्ट्रा निक रूप से दे सकते है. तत्पश्चात, लिंक इनटाइम इंडिया प्रा.लि. द्वारा रिमोट ई-वोटिंग की यह सुविधा बंद की जाएगी.
3. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**
किसी कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कोई व्यक्ति, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के शेयरधारकों की किसी बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने हेतु तब तक पात्र नही होगा, जब तक कि उस बैठक, जिसमें उसे विधिवत रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि नियुक्तव किया गया हो, के अध्यक्ष द्वारा प्रमाणित प्रस्ताव की प्रति बैंक को investoers@centeralbank.co.in पर ई-मेल के माध्यम से बैठक की नियत तारीख से कम से कम चार दिन पूर्व अर्थात शुक्रवार, दिनांक 25 जून, 2021 को सायं: 5.00 बजे या उसके पूर्व तक न भेज दी जाए.
4. बैंक के किसी अधिकारी या कर्मचारी को शेयरधारक के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है.
5. **संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग**
विनियमों के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो मतदान के संबंध में रजिस्टर में पहले नामित व्यक्ति को उसका एकमात्र धारक माना जाएगा. इसलिए यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर हैं, तो पहले नामित व्यक्ति ही बैठक में भाग लेने का हकदार है और केवल बैठक में मतदान करने का पात्र है.
6. शुक्रवार, 4 जून 2021 को बैंक के शेयरधारकों की सूची शनिवार, 5 जून 2021 को और उसके बाद से बैंक खाता संख्या 1787420976, IFSC: CBIN0281067 सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा नरीमन पॉइंट, मुंबई में रुपये 50,000/- (पचास हजार रुपये मात्र) ऑनलाइन अंतरण करके या तदर्थ अनुरोध के साथ ठसेंट्रल बैंक ऑफ इंडियाठ के पक्ष में मुंबई पर देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान कर उप महाप्रबंधक / कंपनी सचिव, प्रधान कार्यालय, 9वीं मंजिल, चंद्रमुखी,नरीमन पॉइंट, मुंबई - 400 021 को प्रेषित करने पर बिक्री के लिए उपलब्ध होगी. इच्छुक उम्मीदवार शेयरधारकों की सूची का निरीक्षण भी कर सकते हैं और वहां से उद्धरण ले सकते हैं.
7. शेयरधारकों का रजिस्टर बैंक के निवेशक सेवा विभाग केंद्रीय कार्यालय में सोमवार से शनिवार सुबह 11 बजे से अपराह्न 3 बजे के बीच (बैंक अवकाश के अलावा) निरीक्षण के लिए खुला है. यदि किसी शेयरधारक को रजिस्टर या उसके किसी हिस्से की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट की आवश्यकता होती है, तो उसे प्रति 1000 शब्दों या उसके आंशिक भाग की प्रतिलिपि के लिए ₹ 5/- की दर से पूर्व भुगतान पर उसकी आपूर्ति की जाएगी.
8. ऐसे शेयरधारक जिनके नाम 4 जून, 2021 को एनएसडीएल/ सीडीएसएल/ आरटीए द्वारा प्रस्तुत सदस्यों/लाभार्थी स्वामियों के रजिस्टर में दर्ज है, वे भाग लेने अर्थात शेयरधारकों के केंद्र सरकार अलावा अन्य शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में नामांकन करने और चुनाव लड़ने के हकदार होंगे. ऐसे शेयरधारक जिनके नाम 23 जून 2021 को एनएसडीएल/ सीडीएसएल द्वारा प्रस्तुत सदस्यों/लाभार्थियों के मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है, वे केंद्र सरकार के अलावा अन्य शेयरधारकों में से निदेशकों के चुनाव में मतदान करने के हकदार होंगे.
9. कोई भी व्यक्ति जो ई-मेल के माध्यम से बैठक की सूचना भेजने के बाद बैंक का सदस्य बनता है और कट-ऑफ तिथि यानी बुधवार, 23 जून 2021 को शेयर धारण करता है, वह जैसा कि यहां ऊपर बताये गए तरीके से यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है.
10. ईजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और वोटिंग के समेकित परिणामों को स्क्रूटिनाइजर की रिपोर्ट के साथ बैंक के ईजीएम में प्रस्ताव पारित होने के दो (2) कार्य दिवसों के भीतर बैंक की वेबसाइट www.centeralbankofindia.co.in और लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट की वेबसाइट पर प्रस्तुत किया जाएगा और बीएसई लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड को सूचित किया जाएगा.
11. असाधारण सामान्य बैठक की सूचना उक्त एमसीए परिपत्रों और सेबी द्वारा 12 मई, 2020 (संशोधित यदि कोई हो) को जारी परिपत्र के अनुसार केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजी जा रही है जिनके ईमेल पते बैंक / डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत हैं. सदस्य ध्यान दें कि असाधारण सामान्य बैठक की सूचना बैंक की वेबसाइट www.centeralbankofindia.co.in पर लिंक निवेशक संबंधों के तहत भी उपलब्ध होगी; स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइटें यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड और बीएसई लिमिटेड। सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम सुविधा के माध्यम से असाधारण सामान्य बैठक में भाग ले सकते हैं और भाग ले सकते हैं.
12. निम्नलिखित को बैंक की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है:
    1. नामांकन फॉर्म और डिक्लेरेशन फॉर्म
    2. व्यक्तिगत जानकारी, घोषणा और वचन जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित किया गया है
    3. सभी प्रासंगिक अधिनियमों, नियमों, विनियमों और अधिसूचनाओं का सार
13. यदि खाताधारक का ई-मेल आईडी पहले ही बैंक / उसका पंजीयक (रजिस्ट्रार) एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट 'आरटीए"/ डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत है तो ई-वोटिंग की लॉग-इन विवरण उस पंजीकृत ई-मेल पते पर भेजे जाएंगे.
यदि शेयरधारक ने अपना ई-मेल आईडी बैंक / उसका रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रान्सफर एजेंट 'आरटीए" / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं किया है,तो असाधारण सामान्य बैठक का नोटिस प्राप्त करने एवं ई-वोटिंग के लिए निम्न' अनुदेशों का पालन करें:
(i) कृपया हमारे आरटीए, लिंक इनटाईम इंडिया प्रा.लि. की वेबसाइट www.linkintime.co.in पर इन्वेसस्टरर सर्विसेस-ई-मेल रजिस्ट्रे शन पर लॉग-इन करें, विवरण भरें और आवश्यक कागज़ात अपलोड कर, सबमिट करें. अथवा
(ii) यदि शेयर डीमेट स्वटरूप में रखें गये है :
शेयरधारक कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपंट ("डीपी") से संपर्क करें और डीपी में प्रचलित और उनके द्वारा सूचित पद्धति के अनुसार डीमेट खाते में ई-मेल आईडी पंजीकृत करें.

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
हस्ताक्षर/-
(आनंद कुमार दास)
उप महाप्रबंधक / कंपनी सचिव

स्थान: मुम्बई
दिनांक: 21.05.2021

'बंदूक भी तेरी, गोली भी तेरी, दिन-तारीख भी तेरी, मगर जीत हमारी' : आशिष शेलार

मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजप-सेनेत वाक्युद्ध

मुंबई, दि. १ (प्रतिनिधी): "मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकांची चर्चा सुरू झाल्यापासून शिवसेना कटकारस्थाने रचत आहे. निवडणुकीतील संभाव्य पराभवाच्या भीतीने पळवाटा शोधण्याचे काम शिवसेना करत आहे. महापालिकेच्या प्रभाग रचनेवर आधी शिवसेनेने आक्षेप घेत नवी प्रभाग रचना करण्याचे प्रयत्न केले. मात्र, यामागे कुठलाही अभ्यास नसल्याने शिवसेनेचा हा प्रयत्न वाया गेला. यासारखे अनेक प्रयत्न करून शिवसेना पालिका निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी अनेक कट रचत आहे. पालिका निवडणुका पुढे ढकलण्यासाठी शिवसेनेच्या वतीने मुख्यत्वे चार बेकायदेशीर प्रयत्न करण्यात आले आणि अजूनही करण्यात येत आहेत. मात्र, भाजप ते प्रयत्न हाणून पाडल्याशिवाय राहणार नाही. 'सामना'मध्ये आजकाल फार 'डायलॉग' वाचायला मिळतात, त्यामुळे त्याला उत्तर द्यायचं झालं तर मी एवढंच सांगू इच्छितो की, 'बंदूक भी तेरी, गोली भी तेरी, दिन-तारीख भी तेरी, दिन कहे दिन, शाम कहे शाम, शिवसेना को परास्त करने

भाजप तयार हैं.'' अशा शब्दांत भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी शिवसेनेवर तोफ डागली आहे. मंगळवारी भाजप प्रदेश कार्यालयात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत आशिष शेलार बोलत होते. यावेळी महापालिका गटनेते प्रभाकर शिंदे, प्रदेश प्रवक्ते केशव उपाध्याय, विश्वास पाठक आदी उपस्थित होते.

शेलार म्हणाले की, "मुंबई महापालिका निवडणुकीबाबत घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीवर आमचे बारीक लक्ष आहे. मागील वर्षी कोरोनाची पहिली लाट आटोक्यात येण्याची शक्यता निर्माण झाली होती, तेव्हा शिवसेनेच्या वतीने मुदतपूर्व निवडणूक घेण्याचा पहिला डाव टाकण्यात आला होता. पण, दुर्दैवाने त्यांचा डाव फसला. त्यानंतर २०१७मध्ये करण्यात आलेली प्रभाग रचना आहे ती असंवैधानिक असल्याची चर्चा जाणीवपूर्वक पसरवली गेली. २०१७ साली झालेली प्रभाग रचना भाजपने आपल्या सोयीनुसार केली, असे सांगून वातावरण निर्माण केले गेले. पण, ती वॉर्ड रचना २०२१च्या जनगणनेच्या आधारावरच असल्याचे दिसून आले व हा प्रयत्न अभ्यास नसल्यामुळे फेल ठरला. त्यासाठी मुंबई महापालिकेतून निवृत्त झालेल्या अधिकाऱ्यांना मोठ्या पगारावर घेण्यात आले होते. कोरोनाची तिसरी लाट येत आहे, त्या पार्श्वभूमीवर आपण सर्वांनी काळजी घेतली पाहिजे ही आमचीसुद्धा भूमिका आहे. तिसऱ्या लाटेमुळे अनेक अडचणी येतील त्यामुळे जनगणना करता येत नाही. नवी मतदार नोंदणी करताना अधिक वेळ लागेल. त्यामुळे महापालिकेला दोन वर्षे मुदतवाढ देण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी शिवसेनेतर्फे सुरू आहे,'' असा आरोप आशिष शेलार त्यांनी केला. दरम्यान, "शिवसेनेने घेतलेली भूमिका काँग्रेस-राष्ट्रवादीला मान्य आहे का हे त्यांनी स्पष्ट करावे,'' असेही शेलार यावेळी म्हणाले.

"मुंबई शहरात असे ३० वॉर्ड आहेत, जे शिवसेना आणि काँग्रेसला आयुष्यात कधीही जिंकता येणार नाहीत. त्यामुळे या वॉर्डांमध्ये फोडाफोडीचं राजकारण सुरू आहे. कायदा आणि कोरोनाचा विचार करून निवडणुका घेण्यासाठी भाजप सदैव तयार आहे,'' असे शेलार यांनी स्पष्ट केले. "'सामना'मध्ये आजकाल फार 'डायलॉग' वाचायला मिळतात, त्यामुळे त्याला उत्तर द्यायचं झालं तर मी एवढंच सांगू इच्छितो की, 'बंदूक भी तेरी, गोली भी तेरी, दिन-तारीख भी तेरी, दिन कहे दिन, शाम कहे शाम, शिवसेना को परास्त करने भाजप तयार हैं।,''' अशा शब्दांत भाजप आमदार आशिष शेलार यांनी शिवसेनेवर जोरदार निशाणा साधला.

"जर महापालिका निवडणुका काही कारणाने पुढे ढकलल्या जात असतील, त्या कालावधीत केलेले सर्व आर्थिक व्यवहार हे स्थायी समितीकडे न पाठवता निवडणूक आयोगाकडे पाठवण्यात यावेत. मुंबई महापालिकेचा २० हजार कोटींचा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प परवानगीसाठी अद्यापही प्रतीक्षेत आहे. यासारख्या प्रकल्पांमधील आर्थिक व्यवहारांना केंद्रस्थानी ठेवून ही कारस्थाने सुरू आहेत, असा आमचा आरोप आहे,'' असे आशिष शेलार यावेळी म्हणाले.

करून दाखवलं म्हणणाऱ्यांनी उत्तर द्यावे

आशिष शेलार यांनी शिवसेनेतर्फे केल्या जाणाऱ्या नालेसफाईच्या दाव्यांची पोलखोल केली. "महापालिकेने ७० कोटी खर्च करून केलेली नालेसफाई संपूर्णतः आभासी आहे. इथे विषय दाव्याचा नाही, वाद्याचा आहे. करून दाखवलं, अशा वल्गना करणाऱ्यांनी मुंबईकरांना मुंबई तुंबू देणार नाही, असा शब्द दिला होता. मात्र, ते दावे फोल ठरल्यानंतर तुम्ही आता त्यावरून बचाव करू नका आणि पळूनही जाऊ नका. पाच लाख मेट्रिक टन गाळ काढला, असा दावा पालिकेने केला आहे. मिठी नदीचा जरी गाळ पकडला तरी तो टाकला कुठे? जिथे तो गाळ टाकण्यात आला ते सरकारी 'डम्पिंग ग्राऊंड' असेल तर गाळ टाकल्याचा फोटो दाखवा, खासगी असेल तर 'सीसीटीव्ही' दाखवा. गाळ कुठे मोजला त्या वजनकाट्याच्या पावत्या दाखवा,'' असे आव्हान देतानाच नालेसफाईतसुद्धा कमिशनखोरी सुरू असल्याचा दावाही आशिष शेलार यांनी केला.

'ओबीसी' आरक्षणासाठी राज्य सरकारनेच जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक

भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांचे प्रतिपादन

मुंबई, दि. १ (प्रतिनिधी): "स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील 'ओबीसीं'चे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्याबद्दल केंद्र सरकारवर दोषारोप करणे निरर्थक आहे. राज्य सरकारनेच मागास आयोग नेमून 'एम्पिरिकल डाटा' तयार करणे आणि त्याआधारे 'ओबीसीं'चे आरक्षण पुन्हा मिळवणे ही जबाबदारी पार पाडणे आवश्यक आहे,'' असे प्रतिपादन भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पुणे येथे केले.

भाजप आ. मुक्ता टिळक यांनी कोरोनाचा सामना करण्यासाठी आमदार निधीतून साहित्य उपलब्ध केले. त्यावेळी चंद्रकांतदादा पाटील बोलत होते. यावेळी

खा. गिरीश बापट व महापौर मुरलीधर मोहोळ उपस्थित होते. आ. मुक्ता टिळक यांनी कोरोनासंदर्भात मदत करण्यासाठी घेतलेल्या पुढाकाराबद्दल चंद्रकांतदादा यांनी मुक्ता टिळक यांचे अभिनंदन केले.

चंद्रकांतदादा म्हणाले की, "'ओबीसीं'ना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पुन्हा आरक्षण मिळण्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने सर्वप्रथम राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन करून त्यांच्यामार्फत जिल्हावार सर्वेक्षण करून 'एम्पिरिकल डाटा' गोळा केला पाहिजे. त्याच्या आधारे 'ओबीसीं'च्या आरक्षणाची आवश्यकता स्पष्ट केली पाहिजे. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाकडून पुन्हा आरक्षण मिळेल. या विषयात केंद्र सरकारचा संबंध येत नाही,'' असेही चंद्रकांतदादा यांनी स्पष्ट केले.

"भाजप महायुती सरकारने नेमलेल्या गायकवाड आयोगाची मुदत संपल्यानंतर गेले सव्वा वर्ष महाविकास आघाडीने नव्याने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन केलेले नाही. दरम्यान, फडणवीस-पवार भेटीवर बोलताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या प्रकृतीची विचारपूस करण्यासाठी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस त्यांना भेटले. ही केवळ सदिच्छा भेट होती,'' असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.

"'तौक्ते' चक्रीवादळामुळे जळगाव जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांचे जबर नुकसान झाले आहे. त्यामुळे तेथील परिस्थितीची पाहणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या विनंतीवरून देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी जळगाव जिल्ह्याला भेट दिली,'' अशी माहिती चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.

मुंबईत सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांकडून २८ लाखांची दंडवसुली

मुंबई : सार्वजनिक ठिकाणी थुंकणाऱ्यांवर नागरिकांवर मुंबई महापालिका प्रशासनाच्या वतीने दंडात्मक कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाई अंतर्गत गेल्या सुमारे सात महिन्यात १४ हजारांपेक्षा अधिक मुंबईकरांकडून सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्याबद्दल तब्बल रुपये २८ लाख ६७ हजार ९०० रुपयांचा दंड वसुल करण्यात आला आहे. उच्च न्यायालयाद्वारे देण्यात आलेल्या आदेशांनुसार ही कारवाई अधिक तीव्र करण्यासोबतच प्रभावी जनजागृती करण्याचे आदेश देखील देण्यात आले आहे.

मुंबईतील दुकानांचे शटर अखेर उघडले

आ. मंगलप्रभात लोढांच्या पाठपुराव्याला यश

मुंबई, दि. १ (प्रतिनिधी) : महाराष्ट्र सरकारने नव्याने राज्यात नवी नियमावली लागू केली आहे. या नियमावलीमुळे मुंबईतील दुकानदारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दुकानदारांच्या समस्येबाबत मुंबई भाजपाध्यक्ष मंगलप्रभात लोढा यांनी सरकारला इशारा दिला होता. "महाराष्ट्र सरकारने येत्या १ जूननंतर दुकाने खुली करण्याची परवानगी दिली नाही, तर भाजप दुकाने खुली करेल,'' असे लोढा यांनी म्हटले होते. त्यामुळे दुकानदारांना मिळालेला दिलासा हे आमदार मंगलप्रभात लोढांच्या पाठपुराव्याला मिळालेले यश आहे, अशी भावना मुंबईतील अनेक सर्वसामान्य दुकानदारांनी व्यक्त केली आहे. दुकानदार, व्यावसायिक व व्यापारी यांच्या उदरनिर्वाहाचा मुद्दा लक्षात घेता आमदार मंगलप्रभात लोढा यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या शिष्टमंडळाने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेऊन दुकाने खुली करण्यासाठी निवेदन दिले होते. अखेर त्यांच्या पाठपुराव्याला यश आल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

राधाकृष्ण नार्वेकर यांच्या निधनावर राज्यपालांचा शोकसंदेश

मुंबई, दि. १ (प्रतिनिधी): राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी ज्येष्ठ पत्रकार राधाकृष्ण नार्वेकर यांच्या निधनाबद्दल शोक व्यक्त केला. ज्येष्ठ पत्रकार, दैनिक सकाळचे माजी संपादक आणि मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे माजी अध्यक्ष राधाकृष्ण नार्वेकर यांचे निधन झाल्याचे वृत्त समजून दुःख झाले. आपल्या प्रदीर्घ वाटचालीत नार्वेकर यांनी विविध विषयांवर जनसामान्यांचे प्रबोधन केले तसेच आपल्या मार्गदर्शनाखाली पत्रकारांच्या पिढ्या घडविल्या. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेपासून आजवरच्या विविध महत्त्वपूर्ण घटनांचे ते साक्षीदार होते. त्यांच्या निधनामुळे महाराष्ट्र एका अभ्यासू पत्रकार व सुहृद व्यक्तिमत्त्वाला मुकला आहे, असे राज्यपाल कोश्यारी यांनी आपल्या शोकसंदेशात म्हटले आहे.

'कोरोना' लसी-औषधे नियंत्रणमुक्त करा

'स्वदेशी जागरण मंच'ची मागणी

मुंबई, दि. १ (प्रतिनिधी): जगातील बहुतेक लोक आज कोरोनाच्या संसर्गाच्या भीतीने त्रस्त आहेत. या संसर्गाचे निदान आणि संसर्ग रोखणारी औषधे आणि लसींचे स्वामित्व (पेटंट) बड्या कंपन्यांच्या हातात असल्याने या गोष्टी सर्वांना सहजपणे उपलब्ध होत नाहीत. माणसाचा जगण्याचा अधिकार सर्वोच्च, मौल्यवान अधिकार आहे. काही कंपन्यांना नफेखोरी करण्यासाठी स्वामित्वाचे अमर्याद अधिकार देऊन कोट्यवधी लोकांच्या जगण्याच्या अधिकारावर टाच येईल, असे होऊ देणे मान्य होणार नाही.

या लसी आणि औषधे स्वस्तात आणि सहजपणे उपलब्ध व्हावीत, यासाठी त्या स्वामित्वमुक्त व्हाव्यात आणि त्यांच्या उत्पादनांचे तंत्रज्ञान हस्तांतरित केले जावे, यासाठी भारतातील लोकांकडून एक देशव्यापी अभियान चालवण्यात येत आहे. कोरोनावरील उपचारावरील औषधांचे उत्पादन अनेक भारतीय कंपन्या करत आहेत. परंतु, समस्या गंभीर स्वरूपाची असल्याने वाढती मागणी पूर्ण करण्यासाठी हे उत्पादन अपुरे ठरत आहे. त्यामुळे कोरोनावरील लसी आणि औषधे यांच्यावरील नियंत्रणमुक्त करून त्यांच्या उत्पादनासाठी सक्षम असलेल्या सर्व औषध उत्पादकांना त्याचे तंत्रज्ञान देण्यात यावे, अशी 'स्वदेशी जागरण मंच'ची मागणी असून मंचच्या वतीने त्यासाठी मोठे अभियानदेखील राबवले जात असून 'डिजिटल' हस्ताक्षर अभियानात आतापर्यंत चार लाख नागरिकांनी स्वाक्षरी केलेली आहे. अशाच एका दुसऱ्या याचिकेवर भारत आणि जगातील २० देशांमधील १,६००हून अधिक शिक्षणक्षेत्रातील नामवंत, विचारवंतांनी स्वाक्षरी करून पुढील मागण्या केल्या आहेत, असे 'स्वदेशी जागरण मंच'च्या वतीने मंगळवारी सांगण्यात आले.

'लोकलमधील महिला सुरक्षा पुन्हा चव्हाट्यावर

मुंबई, दि. १ (प्रतिनिधी): मुंबईमध्ये सध्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावाचा विचार करता अनेक निर्बंध आहेत. खबरदारीचा उपाय म्हणून सरकारने मुंबई लोकलने सर्व सामान्यांना प्रवास करण्यास बंदी आहे. अशामध्ये फक्त आपत्कालीन सेवा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनाच रेल्वे प्रवासासाठी मुभा आहे. अशामध्ये मध्य रेल्वेची सुरक्षा चव्हाट्यावर आणणारी एक घटना समोर आली आहे. एका चोरट्याने मोबाईल हिसकावल्याने त्याचा पाठलाग करताना विद्या पाटील या ३५ वर्षीय महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. मध्य रेल्वेच्या कळवा रेल्वे स्थानकामध्ये शनिवार, दि. २९ मे रोजी हा सर्व प्रकार घडला.

हवाई बंदरातील 'कार्गो' विभागात नोकरी करणाऱ्या विद्या पाटील २९ मे रोजी अंधेरीहून कल्याणकडे जात होत्या. कळवा स्थानकावरून लोकल सुटल्यानंतर एक चोर महिला डब्यात घुसला. काही महिलांच्या हातातून मोबाईल हिसकावल्यानंतर चोराने लोकलमधून उडी मारून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी धाडसी विद्या पाटील यांनी त्याला पकडण्यासाठी लोकलमधून त्याच्या मागे उडी मारली. मात्र, दुर्दैवाने चोराशी झालेल्या झटापटीत चोरट्याने त्या स्थानकाखाली आल्या आणि त्यांचा मृत्यू झाला.

दरम्यान, या घटनेनंतर भाजप प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा वाघ यांनी महिला सुरक्षेबाबत प्रश्न विचारला आहे. "खरंतर संध्याकाळी ६नंतर महिलांच्या डब्यात 'जीआरपी'/'आरपीएफ' जवान असणे बंधनकारक असताना ते का उपस्थित नव्हते? लोकल स्थानकावर घडलेल्या घटनेनंतर महिलांच्या सुरक्षेबाबतची चौकशी होणे गरजेचे आहे,'' असे चित्रा वाघ यांनी म्हटले आहे.

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया
Central Bank of India

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया
मुख्य कार्यालय: चंदरमुखी, नरीमन पॉईंट, मुंबई - ४०० ०२१.

सूचना

याद्वारे सूचित केले जाते की, सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या भागधारकांची विशेष सर्वसाधारण सभा बुधवार, दिनांक ३० जून, २०२१ रोजी स. ११.०० वाजता चंदरमुखी, नरीमन पॉईंट, मुंबई - ४०००२१ येथील बँकेच्या मुख्य कार्यालयामध्ये (सभेचे प्रस्तावित ठिकाण) व्हिडीओ कॉन्फरन्स (व्हीसी) किंवा इतर दृक श्राव्य माध्यमांद्वारे (ओएव्हीएम) निम्नलिखित कामकाज पार पाडण्याकरिता आयोजित करण्यात आलेली आहे:

कार्यसूची बाब: भागधारकांच्या संचालकाची निवडणूक

बँकिंग विनियमन कायदा, १९४९ (यापुढील "विनियमन कायदा" म्हणून उल्लेखित), राष्ट्रीयीकृत बँका (व्यवस्थापन आणि संकीर्ण तरतुदी) योजना, १९७० (यापुढील "योजना" म्हणून उल्लेखित), कायद्याच्या कलम ११ च्या अनुषंगाने बनलेल्या सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (समभाग आणि सभा) विनियमन, १९९८ (यापुढील "विनियमन" म्हणून उल्लेखित) आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या अधिकृत असलेल्या संचालक म्हणून निवडीत घेण्याकरिता भारत सरकारद्वारे जारित दि. २५ मार्च, २०१५ आणि दि. २० जुलै, २०१६ रोजीची मार्गदर्शक तत्त्वांसह (यापुढील "भारत सरकार मार्गदर्शक तत्त्वे" आणि त्यावरील पुढील सुधारणा, जर असल्यास म्हणून उल्लेखित) यासंदर्भात दि. २ ऑगस्ट, २०१९ रोजीच्या अधिसूचना क्र. ईएफ.एमबी/२१.६७.००१/२०१९-२० अन्वये पारित आरबीआयच्या ... संचालकांकरिता 'उचित आणि योग्य' निकष ... दि बँकिंग कंपन्या (उपक्रमांचे संपादन आणि हस्तांतरण) कायदा, १९७० (यापुढील "कायदा" म्हणून उल्लेखित) च्या कलम ९ (३) च्या दृष्टीने खालील ठराव मंजूर करून केंद्र शासनाव्यतिरिक्त बँकेच्या भागधारकांमधून एक संचालक निवडणे:

निम्नलिखित बाबींवर विचार करणे आणि आवश्यक असल्यास त्यामध्ये बदल करून अथवा बदल न करता त्यास विशेष ठराव म्हणून पारित करणे:

"असे प्रस्तावित केले जाते की, कायद्याच्या कलम ९(३)(i), सहवाचित त्याअंतर्गत बनलेल्या योजना, विनियमन आणि आरबीआयचे संबंधित निर्देश आणि भारत सरकारची मार्गदर्शक तत्त्वे, अन्वये केंद्र शासनाव्यतिरिक्त भागधारकांमधून निवडलेला एक संचालक, दि. १ जुलै, २०२१ पासून कार्यालय संभाळण्याकरिता बँकेचा संचालक म्हणून निवडण्यात येत आहे आणि अशा निवडीच्या दिनांकापासून तीन वर्षांचा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत ते कार्यालय संभाळतील.

टिपा:

१. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) किंवा इतर दृक श्राव्य माध्यमांद्वारे (ओएव्हीएम) विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन:
सध्याच्या कोविड-१९ महामारीमुळे, कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय ("एमसीए") द्वारे पारित दि. ५ मे, २०२० रोजीचे परिपत्रक क्र. २०, दि. ८ एप्रिल, २०२० रोजीचे परिपत्रक क्र. १४, दि. १३ एप्रिल, २०२० रोजीचे परिपत्रक क्र. १७, दि. १५ जून, २०२० रोजीचे परिपत्रक क्र. २२, दि. २८ सप्टेंबर, २०२० रोजीचे परिपत्रक क्र. ३३, दि. ३१ डिसेंबर, २०२० रोजीचे परिपत्रक क्र. ३९ आणि दि. १३ जानेवारी, २०२१ रोजीचे परिपत्रक क्र. २ (यापुढील एकत्रितरित्या "एमसीए परिपत्रके" म्हणून उल्लेखित) सह वाचण्यात भारतीय प्रतिभूती आणि विनिमय मंडळ (सेबी) परिपत्रक क्र. सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी१/सीआयआर/पी/२०२०/७९ दिनांकित १२ मे, २०२० आणि सेबी/एचओ/सीएफडी/सीएमडी२/सीआयआर/पी/२०२१/११ दिनांकित १५ जानेवारी, २०२१ द्वारे सामायिक ठिकाणी सदस्यांच्या प्रत्यक्ष उपस्थितीशिवाय व्हीसी किंवा ओएव्हीएम द्वारे विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. सदर एमसीए परिपत्रके आणि सेबी (सूचिबद्धता दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, २०१५ चे अनुपालन करताना, बँकेच्या सदस्यांची विशेष सर्वसाधारण सभा व्हीसी/ओएव्हीएमद्वारे आयोजित करण्यात आली आहे. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (व्हीसी) किंवा इतर दृक श्राव्य माध्यमांद्वारे (ओएव्हीएम) विशेष सर्वसाधारण सभेत उपस्थित राहण्याच्या प्रक्रियेच्या तपशीलाकरिता, कृपया विशेष सर्वसाधारण सभेची सूचना पहावी, जी भागधारकांना ई-मेल करण्यात आली आहे आणि बँकेची वेबसाईट म्हणजेच www.centralbankofindia.co.in वर "इन्व्हेस्टर रिलेशन्स" लिंक अंतर्गत अपलोड करण्यात आली आहे.

२. रिमोट ई-मतदान
कंपनी (व्यवस्थापन आणि प्रशासन) विनियमन, २०१४ चा नियम २० दुरुस्ती केल्यानुसार सह वाचण्याच्या सेबी (सूचिबद्धता दायित्वे आणि प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियमन, २०१५ च्या नियमन ४४ दुरुस्ती केल्यानुसार च्या अनुपालनात, बँक मतदानाच्या पर्यायी मार्ग म्हणून रिमोट ई-मतदान सुविधा प्रदान करीत आहे ज्याद्वारे सदस्य त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देऊ शकतील. बँकेने रिमोट ई-मतदान सुविधा देण्याकरिता लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लिमिटेड, रजिस्ट्रार आणि बँकेचे भाग हस्तांतरण एजंट यांच्यासोबत आवश्यक व्यवस्था केलेली आहे. रिमोट ई-मतदान कालावधी रविवार, दि. २७ जून, २०२१ रोजी सकाळी १० .०० वाजता सुरू होईल आणि मंगळवार दि. २९ जून, २०२१ रोजी सायं. ५.०० वा. समाप्त होईल. या कालावधीदरम्यान कट-ऑफ दिनांकास म्हणजेच बुधवार, २३ जून, २०२१ रोजी, प्रत्यक्ष स्वरूपात किंवा डीमटेरिअलाईझ्ड स्वरूपात भाग धारण करणारे बँकेचे भागधारक त्यांचे मत इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने देऊ शकतील. रिमोट ई-मतदान यंत्रणा त्यानंतर लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लिमिटेडद्वारे बंद केली जाईल.

३. प्राधिकृत प्रतिनिधीची नियुक्ती :
बँकेचे भागधारक कोणत्याही कंपनी किंवा कॉर्पोरेट बॉडीच्या वतीने प्राधिकृत प्रतिनिधीच्या रुपात कोणीही व्यक्ती सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाच्या भागधारकांच्या सभेमध्ये उपस्थित होण्यास किंवा मतदान करण्यास तोपर्यंत पात्र होऊ शकत नाही, जोपर्यंत, त्याला त्यांच्यावतीने प्राधिकृत प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त केले गेले आहे त्या ठरावाची अध्यक्षांद्वारे प्रमाणित प्रत चंदरमुखी, नरीमन पॉईंट, मुंबई ४०००२१ येथे स्थित बँकेच्या मुख्य कार्यालयातील सभेच्या निश्चित दिनांकापूर्वी कमीत कमी चार दिवस आधी म्हणजेच शुक्रवार, दिनांक २५ जून, २०२१ रोजी सायं. ५.०० वाजता किंवा त्यापूर्वी जमा करावयास हवे.

४. बँकेचा अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यास भागधारकाचा प्राधिकृत प्रतिनिधी म्हणून नियुक्त करता येणार नाही.

५. संयुक्त धारकांच्या अधिकारांचा वापर
विनियमनांच्या विनियमन १० नुसार, जर कोणताही भाग दोन किंवा अधिक व्यक्तींच्या नावे असल्यास, नोंदपटामध्ये पहिले नाव असलेली व्यक्ती, मतदानाच्या संदर्भात, त्याचे एकमेव धारक असल्याचे मानले जाईल. म्हणून जर भाग संयुक्त धारकांच्या नावे असल्यास, फक्त पहिले नाव असलेली व्यक्तीच सभेस उपस्थित राहू शकेल आणि सभेमध्ये मतदान करण्यास पात्र राहील.

६. शुक्रवार दि. ४ जून, २०२१ रोजीनुसारची बँकेच्या भागधारकांची यादी शनिवार, दि. ५ जून, २०२१ रोजी आणि पासून पुढे रु. ५०,०००/- (रुपये पन्नास हजार मात्र) सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, नरिमन पॉईंट शाखा, मुंबई च्या बँक खाते क्रमांक ... येथे ऑनलाईन हस्तांतरण केल्यानंतर किंवा "सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया" च्या नावे मुंबई येथे देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारे भरणा केल्यानंतर व त्यासह उप महा व्यवस्थापक / कंपनी सचिव, सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, मुख्य कार्यालय, ९ वा मजला, चंदरमुखी, नरिमन पॉईंट, मुंबई - ४०० ०२१ यांच्या नावे लिखित पत्रव्यवहार विक्रीकरिता उपलब्ध होईल. इच्छुक उमेदवार भागधारकांची यादी त्यासह देखील भरून आणि त्यामधून सारांश घेऊ शकतात.

७. भागधारकांचे नोंदपट बँकेच्या इन्व्हेस्टर सर्व्हिसेस डिपार्टमेंट केंद्रीय कार्यालय येथे सोमवार ते शनिवार स. ११ ते दु. ३ या वेळेत (बँकेच्या सुट्टीच्या दिवसांव्यतिरिक्त) तपासणीकरिता खुले असेल. जर एखाद्या भागधारकास नोंदपटाची किंवा त्याच्या भागाची प्रत किंवा संगणक प्रिंट हवी असल्यास, प्रति १००० शब्द किंवा त्याची नक्कल करावी लागणारा अंशात्मक भाग रु. ५/- चा पूर्वभरणा केल्यानंतर त्यास पुरविण्यात येईल.

८. एनएसडीएल/सीडीएसएल/आरटीए द्वारे दि. ४ जून, २०२१ रोजी सुसज्ज सदस्य/लाभधारक मालकांच्या नोंदपटावर ज्या भागधारकांचे नाव उपस्थित आहे ते भाग घेण्याकरिता, म्हणजेच केंद्र सरकारव्यतिरिक्त भागधारकांमधून संचालकांच्या निवडीमध्ये नामनिर्देशन आणि निवडणूक लढविण्याकरिता पात्र असतील. एनएसडीएल/सीडीएसएल/आरटीए द्वारे दि. २३ जून, २०२१ रोजी सुसज्ज सदस्य/लाभधारक मालकांच्या नोंदपटावर ज्या भागधारकांचे नाव उपस्थित आहे ते केंद्र सरकारव्यतिरिक्त भागधारकांमधून संचालकांच्या निवडीमध्ये मतदान करण्याकरिता पात्र असतील.

९. सभेची सूचना पाठविल्यानंतर जर एखादा व्यक्ती बँकेचा सभासद झाला असेल आणि कट-ऑफ दिनांकास म्हणजेच बुधवार, दि. २३ जून, २०२१ रोजी भागधारणा करीत असेल, त्याने वर उल्लेखिलेल्या पद्धतीने युजर आयडी आणि पासवर्ड मिळवावा.

१०. स्क्रुटिनायझर यांच्या अहवालासह रिमोट ई-मतदान आणि ईजीएमदरम्यान झालेल्या मतदानाचा एकत्रित निकाल बँकेची वेबसाईट www.centralbankofindia.co.in आणि लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लिमिटेडची वेबसाईट येथे बँकेच्या ईजीएममध्ये ठराव मंजूर झाल्यापासून आणि बीएसई लिमिटेड आणि नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेडला कळविल्यापासून दोन (२) कामकाजाच्या दिवसांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात येईल.

११. उपरोल्लेखित एमसीए परिपत्रके आणि सेबीद्वारे दि. १२ मे, २०२० रोजी पारित परिपत्रक (दुरुस्ती केल्यानुसार, जर असल्यास) अनुसार बँक/डिपॉझिटरीकडे ज्यांचे ईमेल पत्ते नोंदणीकृत आहेत, अशा सदस्यांना विशेष सर्वसाधारण सभेची सूचना इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने पाठविण्यात आली आहे. सदस्यांनी नोंद घ्यावी की, विशेष सर्वसाधारण सभेची सूचना बँकेची वेबसाईट म्हणजेच www.centralbankofindia.co.in वर "इन्व्हेस्टर रिलेशन्स" लिंक अंतर्गत आणि स्टॉक एक्सचेंज म्हणजेच नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया आणि बीएसई लिमिटेडच्या वेबसाईट्स वर देखील उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत.

१२. खालील गोष्टी देखील बँकेच्या वेबसाईटवर उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत:
१. नामनिर्देशन अर्ज आणि उद्घोषणा अर्ज
२. व्यक्तिगत माहिती, उद्घोषणा आणि आरबीआयद्वारे विहीत केल्यानुसार हमी
३. सर्व संबंधित कायदे, नियम, विनियमन आणि अधिसूचनांचे सारांश

१३. ईमेल आयडीचे नोंदणीकरण:
जर भागधारकाचा ईमेल आयडी यापूर्वीच बँक/त्यांचे रजिस्ट्रार आणि भाग हस्तांतरण एजंट (आरटीए)/डिपॉझिटरीज यांच्याकडे नोंदणीकृत असल्यास, नोंदणीकृत ईमेल पत्त्यावर लॉग इन तपशील पाठविण्यात येतील.
जर भागधारकाने त्यांचा/तिचा/त्यांचा ईमेल पत्ता बँक/त्यांचे रजिस्ट्रार आणि भाग हस्तांतरण एजंट (आरटीए)/डिपॉझिटरीज यांच्याकडे नोंदणीकृत केलेला नसल्यास किंवा लाभांश, भविष्यात जर घोषित करण्यात आल्यास, प्राप्त करण्याकरिता बँक खाते मँडेट अद्यावत केलेले नसल्यास, खालील सूचनांचे पालन करावे:
(i) प्रत्यक्ष स्वरूपात: आरटीए, लिंक इनटाईम इंडिया प्रा. लि. ची वेबसाईट www.linkintime.co.in वर इन्व्हेस्टर सर्व्हिसेस > ईमेल रजिस्ट्रेशन अंतर्गत लॉग इन करून तपशील भरावा आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करून सबमिट करावे, किंवा
(ii) डीमॅट स्वरूपात ठेवलेले असल्यास:
भागधारकांनी कृपया डिपॉझिटरी पार्टिसिपेंट ("डीपी") यांना संपर्क करावा आणि डीपीद्वारे प्रचलित आणि सल्ला दिलेल्या प्रक्रियेनुसार डिमॅट अकाउंटमध्ये ईमेल पत्ता आणि बँक खाते तपशील नोंदवावा.

ठिकाण : मुंबई
दिनांक: २१.०५.२०२१

संचालक मंडळाच्या आदेशाद्वारे
सही/-
आनंद कुमार दास
उप महा व्यवस्थापक/
कंपनी सचिव